an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 9th May, 2016.

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 9 मई, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:

1. वÂर्ष 2016-17 के लिए बजट (उत्तराखंड) का प्रस्तुतीकरण;

2. वÂर्ष 2016-17 के लिए बजट (उत्तराखंड) पर सामान्य चर्चा;

3. वÂर्ष 2016-17 के लिए अनुदान की मांगों (उत्तराखंड) पर चर्चा और मतदान;

4. उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना- अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए;

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में यान हरण निवारण विधेयक, 2016 पर विचार और पारित करना;

6. उत्तराखंड राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 27 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोÂषणा का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा;

7. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात बाल श्रम (प्रतिष्Âाोध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 पर विचार और पारित करना;

8. लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सहमति देना; और

9. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राजेन्द्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 पर विचार और पारित करना।

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I request you to include following issues for discussion in the List of Business for the next week:

1. *Ghar Ghar Main Sauchalaya* in Mumbai and urban metro cities. Urban Development Ministry is to execute time bound action plan/programme for individual toilet block under *Swachch Bharat Abhiyan* in corporate township;
2. Aggressive installation awareness of solar power resulting into drastic fall in the solar power cost. Recent bidding in India shows Rs.4.37 per unit while in Dubai solar power cost came down to Rs.2 per unit. Government must take up aggressive steps to achieve our hon. Prime Minister's dream to have one lakh megawatt solar power in India.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विÂषयों को शामिल करने हेतु सबमिशन पेश करता हूं।

1. माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान केन्द्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले बजट की तरफ आकर्Âिषत कराना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले बजट को 32औ से बढ़ा कर 42औ कर दिया गया है जबकि पूरे देश में करोड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं उनकी सहायिकाएं, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा अनुदेशक, सरकारी विद्यालयों में भोजन बनाने वाले/वाली रसोइयों, चौकीदारों, जानवरों का इलाज करने वाले पैरावेट, विशेÂष शिक्षक, उर्दू शिक्षक, आशा बहुओं, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, होमगार्ड्स, पी.आर.डी. के जवान, स्ववित्तपोÂिषत महाविद्यालयों के शिक्षक तथा राज्यों के सभी विभागों में कार्य करने वाले संविदाकर्मियों को न्यूनतम वेतन उनके पदों के अनुसार देने के लिए राज्यों को 10औ बढ़ाए गए बजट में से देना सुनिश्चित करने के लिए विधेयक सदन में लाया जाए।

2. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग किस-किस मद में राज्यों की सरकारें करती हैं, इसकी जवाबदेही देने के लिए सुनिश्चित करने का विधेयक सदन में लाया जाए।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष जी, निम्नलिखित विÂषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ा जाए -

1. हीरक चतुर्भुज रेल परियोजना का उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में ललितपुर से रामटेक तक रेल लाइन विस्तार करने का कार्य प्रारंभ हो ताकि उत्तर से दक्षिण की दूरी 200 कि.मी. कम हो सके।

2. नर्मदा नदी से केन नदी को जोड़ कर कोपरा-व्यरमा-सोनार नदी में जल पहुंचा कर बुंदेलखंड क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई की समस्या से निजात दिलाएं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The following items may be included in the List of Business commencing from 9th of May, 2016:

1. Pyrotechnic tragedy at Puttingal Devi Temple at Paravoor, Kollam in my constituency in which 109 people lost their lives;
2. Conducting National Entrance-cum-Eligibility Test for admission to undergraduate Medical and Dental Course in two phases directed by the Supreme Court.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विÂषयों को अगले सप्ताह के कार्य सूची में शामिल किया जाए -

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत जादुगोड़ा UCIL कम्पनी है जो भारत सरकार के अधीन है। यहां पर अति महत्वपूर्ण यूरेनियम खनिज पदार्थ पाया जाता है। ये माइंस सबसे पुरानी जादुगोड़ा के नाम से है लेकिन ये कम्पनी विगत दो वÂर्षों से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण बंद पड़ा है। जिससे वहां पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में टाटा कम्पनी है जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच में स्थित है तथा बड़ी कम्पनी होने के कारण प्रतिदिन बड़ी-बड़ी हजारों गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है तथा इसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 40 से 50 हजार है। जिसके कारण शहर में जगह-जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगी रहती है और जिसके कारण औसतन प्रति वÂर्ष 400 दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें 300 लोगों की मौत होती है। पूरे टाटा शहर में एक भी फ्लाई ओवर नहीं रहने के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि वहां के लोगों की यह मांग वर्षों पुरानी है।

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी जी।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : क्या 377 पर बोलना है?

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह 377 नहीं है। यह सबमिशन है। आपको सबमिशन दी गयी होगी।

श्री गोपाल शेट्टी: मेरे पास जो कागज़ हैं, उन्हें देखा है। उसमें इसके कागज़ नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप उसे ढूंढ़ लीजिए। आपको बाद में बुलाती हूं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदया।

माननीय अध्यक्ष : गोपाल शेट्टी जी, क्या आपको वे कागज मिल गए?

श्री गोपाल शेट्टी: जी।

माननीय अध्यक्ष : अश्विनी जी, आप उनके बाद बोलिएगा।

गोपाल शेट्टी जी, बोलिए। थोड़े-से अलर्ट रहना।

श्री गोपाल शेट्टी: महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विÂषयों को सम्मिलित किया जाएः -

1. महाराÂष्ट्र सरकार ने निदेशक (एफ.सी.डी.), 13वां वित्त आयोग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य में वाटर सेक्टर मैनेजमेंट (जल प्रबंधन क्षेत्र) के लिए 92 करोड़ रुपए का अनुदान प्रति वÂर्ष प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने से संबंधित विÂषय।

2. महाराÂष्ट्र राज्य को पिछले काफी समय से सूखे का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कृÂिष फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और किसान भी भूखे मरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। महाराÂष्ट्र राज्य में किसानों ने एक बहुत बड़ी तादाद में कृÂिष फसल बर्बाद होने के कारण अपनी जानें दी हैं। महाराÂष्ट्र राज्य के प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक पैकेज स्वीकृत किए जाने से संबंधित विÂषय।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदया, मैं अगले सप्ताह की विÂषय सूची में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जनहित में सम्बद्ध करना चाहता हूं :-

1. राÂष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का कोई भी केन्द्र बिहार में नहीं है। अतएव महर्Âिष विश्वामित्र की तपोभूमि हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर में वेद अध्ययन हेतु देवभाÂषा संस्कृत संस्थान का एक केन्द्र तथा काशी हिन्दू वि0 वि0 की भी एक शाखा बक्सर (मिनी काशी) में स्थापित की जाए, जिससे बक्सर सहित शाहाबाद क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राएं जो काशी हिन्दू वि0 वि0 में पठन-पाठन करते हैं तथा जो वहां जाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें भी उच्चतर शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा जिससे वे गौरवान्वित होंगे।

2. हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर शहर अन्तर्गत पुराना सदर अस्पताल को विगत पांच-छः वÂर्षों से बन्द कर शहर से काफी दूर सुनसान जगह में नया सदर अस्पताल स्थानान्तरित किया गया है जिससे शहर वासियों को चिकित्सा कराने में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। विशेÂषकर रात्रि में अचानक किसी की तबीयत खराब होने पर तथा महिलाओं के प्रसव हेतु काफी कÂट उठाना पड़ता है।

अतएव जनहित में केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राÂष्ट्रीय (शहरी) स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एव0एम0) अन्तर्गत पुराना सदर अस्पताल परिसर में "शहरी प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र" तथा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए अत्याधुनिक संयंत्र के साथ एक "ट्रॉमा सेन्टर" भी स्थापित किया जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, निम्नलिखित विÂषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए।

1. भोजन, पेय पदार्थ, दवाइयों और अन्य उपभोक्ता पदार्थों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के उपयोग की सुविधा अब इंसान के अस्तित्व के लिए खतरा बन गयी है। नान बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से संग्रहित सामग्री, मिट्टी और पानी में हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं का रिसाव करता है जो कैंसर, जन्म दोÂष, टाइप 2 मधुमेह, श्वसन और हृदय की बीमारियों का कारण बनता है, जो कि स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। अतः प्लास्टिक उत्पादों की पूर्ण बंदी हेतु सख्त नियम बनाया जाएं।

2. वÂर्ष 2011 से 2015 तक संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में CSAT का भेदभावकारी पेपर जारी रहा जिसका व्यापक विरोध ग्रामीण पृÂष्ठभूमि और मानविकी विÂषय के छात्रों द्वारा निरंतर किया गया। वर्ष 2015 में यूपीएससी के नोटिफिकेशन में CSAT पेपर को क्वालीफाइंग कर दिया गया जो कि स्वागतयोग्य कदम था, लेकिन जिन छात्रों ने अपना मूल्यवान समय एवं प्रयास इन 5 वÂर्षों में खो दिया उनके अवसर एवं हित की अनदेखी न्यायोचित नहीं होगी। अतः इन प्रभावित ग्रामीण पृÂष्ठभूमि के छात्रों को यूपीएससी की परीक्षा में पुनः तीन अवसर प्रदान करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

श्री मुकेश राजपूत (फरूखाबाद) : महोदया, कृपया मेरे निम्नलिखित कथन को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

हमारे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली गंगा, रामगंगा व काली नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए बंधा बनाए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

गंगा नदी में शहर का दूÂिषत जल न जाए इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने के सन्दर्भ में।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : महोदया, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विÂषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं :-

1. मेरा जिला नागौर एवं लोक सभा क्षेत्र शिक्षा की दÂिष्ट से पिछड़ा हुआ है। पिछले नौ वÂर्षों से केन्द्रीय विद्यालय का प्रस्ताव विचाराधीन है। पन्द्रह एकड़ जमीन केन्द्रीय विद्यालय के नाम से नामान्तरित एवं वैकल्पिक भवन की व्यवस्था कर दी गई है। अतः 35 लाख की आबादी एवं सैनिकों की भूमि में केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार किया जाए।

2. जिले में ग्रामीण आबादी ग्रामों के साथ-साथ ढ़ाणियों में बस रही है। खेतों पर ही लोगों ने घर बना रखे हैं। इन ढ़ाणियों में बच्चों की पढ़ाई, रात्रि में उजाला एवं घरेलू कार्य हेतु बिजली की आवश्यकता है। अतः या तो ढ़ाणियों को विद्युत सिंगल फेस कनेक्शन से जोड़ा जाए अथवा 90 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर सोलर सिस्टम की व्यवस्था दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ लिए जाने का कष्ट करें।